



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31 10 श्रावण 1940 (श0)
पटना, बुधवार, 1 अगस्त 2018 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 3-4
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 5-8

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचना

13 जुलाई 2018

सं० 236 नि०—दिनांक 21.07.2018 को झंझारपुर में स्थापित होने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए श्री त्रिलोकी दुबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी को दिनांक 21.07.2018 के प्रभाव से झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
बी० बी० पाठक, महानिबंधक।

The 13th July 2018

No. 236A--Sri Triloki Dubey, Additional District and Sessions Judge, Madhubani is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Jhanjharpur on the establishment of the Court of Additional District and Sessions Judge at Jhanjharpur on 21.07.2018.

By Order of the High Court,
B. B. Pathak, Registrar General.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2018

सं० 05/स० स्था० (नि०प०)— 07/97-3142—बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1981 की धारा 4 के अधीन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)/अस्पष्ट, अपर सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2018

सं० स्था.-1-07/2011/356/रा.,—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के संलेख ज्ञापांक-327, दिनांक 28.04.2016 में सन्निहित प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 28.04.2016 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-11 में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-स्था.-1-07/2011-743/रा., दिनांक 05.10.2016 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के विभिन्न 22 (बाईस) सृजित पद उर्दू निदेशालय को अन्तरित किये जा चुके हैं।

2. उक्त अधिसूचना संख्या-743/रा., दिनांक 05.10.2016 की कड़िका-2 के अनुपालन में कार्यालय परिचारी के रिक्त 02 (दो) पद उर्दू निदेशालय को अन्तरण किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1002---I, Swechcha D/O Shambhu Kumar Roy born on 21.01.1989 residing at 102, Ramavatar Residency, North Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna have changed my name to Swechcha Roy vide affidavit no.-1134, dated 20.01.2018 at Patna.

Swechcha.

सं० 1020—मैं, अभिषेक, पिता- अमरेन्द्र कुमार दत्ता, पता- सजीव निवास, रेलवे कॉलोनी, अवधपुरी, दीघा, पटना, बिहार। शपथ पत्र संख्या- 9207 दिनांक 28/05/2018 के द्वारा अब से मैं अभिषेक कुमार दत्ता के नाम से जाना जाऊंगा।

अभिषेक।

No. 1021---मैं दीपिका कुमारी, पिता श्री दीपक कुमार रक्षित, पति श्री चन्दन कुमार, बेलबाग कॉलोनी, थाना—बेतिया मु., जिला—प.चम्पारण (बिहार) अनुमंडल दण्डाधिकारी, बेतिया के शपथ—पत्र संख्या—7973, दिनांक 17.04.2018 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दीपिका कुमारी दर्ज है। विवाह के पश्चात मेरा नाम दीपिका देवराय हो गया है। भविष्य में मैं दीपिका देवराय के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

दीपिका कुमारी।

सं० 1041—मैं सुमन रानी पति शशि भूषण राय पिता राम उद्गार सिंह पता राजीव नगर, रोड नं०—21 मकान सं०—31 पटना बिहार शपथ पत्र सं० 83 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा अब से सुमन राय के नाम से जानी जाऊंगी।

सुमन रानी।

No. 1041—I, SUMAN Rani W/o Shashi Bhushan Ray D/O Ram Udgar Singh R/O Rajiv Nagar Road, No. 21 H. No. 31, Patna. Vide Affidavit No. 083 dated 28.04.2018 will be known as Suman Ray.

SUMAN Rani.

No. 1065—I, Krishna Deva Raya, S/o Late Parichhan Raya, aged about 47 Year, Res. of vill+P.O.-Sathiauta, P.S Bhagwanpur, Dist-Vaishali do hereby Solemnly affirm and Declare vide

affidavit No. 9865 dated 15-06-2018 that know I known and identify as KRISHNA DEV RAY S/o Late PARICHHAN RAY.

Krishna Deva Raya.

सं० 1066—मैं, **रूपल**, पुत्री श्री हेमन्त कुमार, 302, एम. एस. स्मृति कॉम्प्लेक्स, आशियाना-दीघा रोड, पटना-25, पटना सदर की निवासी हूँ। Affd. No. - 15190 dated 13.07.2018 के आलोक में, मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम अब रूपल वर्मा हो गया है। आज से मैं रूपल वर्मा के नाम से जानी जाऊँगी।

रूपल ।

No. 1066—I, **RUPAL** D/O Sri Hemant Kumar R/O 302, M.S. Smriti Complex, Ashiana Digha Road, Patna-25 declare vide Affidavit No.—15190 dated 13.07.2018 have changed my name to Rupal Verma.

RUPAL.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई 2018

सं० 16/एम.1-55/2016-949(आ०चि०)—डॉ० अनिल कुमार सिंह, व्याख्याता, राजकीय आर०बी०टी०एस० हामियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर द्वारा विभागीय अनुमति के बिना दिनांक 07.02.2018 से 14.02.2018 तक विदेश यात्रा (दुबई, यू०ए०ई०) की गयी। डॉ० सिंह का यह कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इस संबंध में डॉ० सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को तथ्यहीन पाते हुए उनके अवकाश याचना को अस्वीकृत करते हुए NO WORK NO PAY के आधार पर दिनांक 07.02.2018 से 14.02.2018 तक का वेतन भुगतान नहीं करने एवं उक्त अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है।

डॉ० सिंह की स्वेच्छाचारिता आचरण के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग V(14)(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव।

सं० 15/सी 2-05/2017-1244

शिक्षा विभाग

संकल्प

18 जुलाई 2018

विषय :-उच्च शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित बांग्ला अकादमी, पटना में कार्यरत कर्मियों को अन्य अकादमियों की भाँति पंचम वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतनानुदान तात्कालिक प्रभाव से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न भाषायी अकादमी स्थापित एवं संचालित है। इन अकादमियों में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान में समरूपता का अभाव है। इन अकादमियों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन, प्रचार-प्रसार, साहित्य का संकलन प्रोत्साहन, साहित्यकारों का सम्मान, अनुसंधान एवं अन्वेषण आदि के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई है।

2. विभिन्न अकादमियों से उनके कर्मियों के वेतन अनुदान भुगतान हेतु समर्पित किए गए बजट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकांश अकादमियों में कर्मियों को पाँचवे वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतन अनुदान भुगतान किया जा रहा है। परंतु, बांग्ला अकादमी में अब तक पाँचवे वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतन भुगतान नहीं हो रहा है।

3. बांग्ला अकादमी के एक कर्मी द्वारा अन्य अकादमी के सदस्य पंचम वेतन में भुगतान की माँग हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका (CWJC No. 11264/2016 देवव्रत सान्याल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं अवमाननावाद (MJC No. 4236/2016) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए

निष्पादित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रश्नाधीन मॉग हेतु एक नयी याचिका CWJC No. 10067/2017 देवव्रत सान्याल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य माननीय न्यायालय में लंबित है। उपर्युक्त सभी सदृश्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में बंगला अकादमी को अन्य अकादमियों की भाँति पंचम वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य राशि की स्वीकृति किया जाना आवश्यक है।

4. उच्च शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित बंगला अकादमी, पटना में कार्यरत कर्मियों को अन्य अकादमियों की भाँति पंचम वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतनानुदान की स्वीकृति तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. दिनांक 12.06.2018 की बैठक में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 5th July 2018

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/2018-2539----WHEREAS, It is alleged that **Sri Anand Kumar S/o Late Braj Bhushan Prasad the then District Welfare Officer, Vaishali, Village - Belaur, P.S. - Udwant Nagar, District - Bhojpur At Present Address - C/o Anjani Kumar Sinha, Gokul Nagar, Lohiya Path, Jagdeopath, P.S. - Rupaspur, District - Patna** while holding the post of **Sri Anand Kumar S/o Late Braj Bhushan Prasad the then District Welfare Officer, Vaishali** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 95/2016 dated 23-09-2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Anand Kumar S/o Late Braj Bhushan Prasad the then District Welfare Officer, Vaishali, Village - Belaur, P.S. - Udwant Nagar, District - Bhojpur At Present Address - C/o Anjani Kumar Sinha, Gokul Nagar, Lohiya Path, Jagdeopath, P.S. - Rupaspur, District - Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, *Principal Secretary.*

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 5th July 2018

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/2017-2540-WHEREAS, It is alleged that **Sri Dadan Prasad S/o Late Kapildev Prasad, the then Ranger, Muzaffarpur, Village - Tukulia,**

P.S. - Govindganj, District - East Champaran At Present Address - D/56, People's Co-operative Colony, Kankarbagh, P.S. - Kankarbagh, District-Patna while holding the post of **Sri Dadan Prasad S/o Late Kapildev Prasad, the then Ranger, Muzaffarpur**, and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 13/2012 dated 07-02-2012.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Dadan Prasad S/o Late Kapildev Prasad, the then Ranger, Muzaffarpur, Village - Tukulia, P.S. - Govindganj, District - East Champaran At Present Address - D/56, People's Co-operative Colony, Kankarbagh, P.S. - Kankarbagh, District-Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, *Principal Secretary.*

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 5th July 2018

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-03/2018-2541-WHEREAS, It is alleged that **Sri Nagendra Singh S/o Late Ramchandra Singh the then Head Assistant, Established Section, Colecteriat Office, Gopalganj, Permanent Address :- Village-Barkuiya, Tiwari Tola, P.S. - Barauli, District - Gopalganj, At Present Ward No.-26, Haziapur Giri Tola, P.S.-Town, Dist.- Gopalganj** while holding the post of **Sri Nagendra Singh S/o Late Ramchandra Singh the then Head Assistant, Established Section, Colecteriat Office, Gopalganj** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 14/2015 dated 14-10-2015.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Nagendra Singh S/o Late Ramchandra Singh the then Head Assistant, Established Section, Colecteriat Office, Gopalganj, Permanent Address :- Village-Barkuiya, Tiwari Tola, P.S. - Barauli, District - Gopalganj, At Present Ward No.-26, Haziapur Giri Tola, P.S.-Town, Dist.- Gopalganj** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, *Principal Secretary*.

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 5th July 2018

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/2018-2542--WHEREAS, It is alleged that **Sri Syed Sadik Hussain S/o Late Ashif Hussain the then Assistant Secretary-cum-Private Secretary (Retired), Bihar State Madarsa Education Board, Patna, Village-Jamuar, P.S+Distt.-Sheikhpura, At Present Magistrate Colony Aashiyana Nagar, P.S-Rajiv Nagar, Distt.-Patna** while holding the post of **Sri Syed Sadik Hussain S/o Late Ashif Hussain the then Assistant Secretary-cum-Private Secretary (Retired)** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 32/2015 dated 30-04-2015**.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Syed Sadik Hussain S/o Late Ashif Hussain the then Assistant Secretary-cum-Private Secretary (Retired), Bihar State Madarsa Education Board, Patna, Village-Jamuar, P.S+Distt.-Sheikhpura, At Present Magistrate Colony Aashiyana Nagar, P.S-Rajiv Nagar, Distt.-Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, *Principal Secretary*.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>